भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 802

14 दिसम्बर, 2022 को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण

802.# डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में अब तक कितनी सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है;
- (ख) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में काम कर रही सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण किया है; और
- (ग) यदि हाँ, तो इसके परिणाम स्वरूप इनमें क्या-क्या बदलाव नज़र आए हैं ?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग) : ₹2,516 करोड़ के कुल बजटीय परिव्यय से देशभर में, मध्य प्रदेश राज्य के पैक्स सहित, 63,000 कार्यशील प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (PACS) के कंप्यूटरीकरण की एक परियोजना को आर्थिक कार्य मंत्रिमंडलीय समिति ने दिनांक 29 जून, 2022 के अपने निर्णय द्वारा स्वीकृत कर दिया है।

इस परियोजना में सभी कार्यशील प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों को ERP (एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन सॉफ्टवेयर पर लाना तथा उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड के साथ जोड़ना शामिल है। प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों के कंप्यूटरीकरण से उनके कार्यों में दक्षता वृद्धि, ऋणों का त्वरित संवितरण सुनिश्चित होना, लेनदेन लागत में कमी, भुगतानों के असंतुलनों में कमी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों व राज्य सहकारी बैंकों के साथ निर्बाध लेखांकन और पारदर्शिता में बढ़ोत्तरी जैसे विभिन्न लाभ प्राप्त होंगे।